प्रकाशन का गौरवाशाली 14वाँ वर्ष

दिव्य हिमगिरि

हिमालयी राज्यों की पहली साप्ताहिक पत्रिका

नज़र सब पर

वर्ष 14 | अंक 37 | मूल्य 15 रुपये | 02-08 फरवरी, 2025

उपलब्धियां और अतुलनीय फैसलों से सीएम धामी के हौसले बुलंद

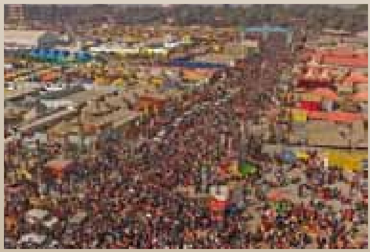

बेहतर इंतजामों के बावजूद महाकुंभ में लग गया ''हादसों का ग्रहण''

मिडिल क्लास पर मेहरबान बजट

12 लाख की कमाई पर टैक्स की टेंशन खत्म

SGRRU

SHRI GURU RAM RAI UNIVERSITY
DEHRADUN, UTTARAKHAND

Recognized by UGC u/s 2(f)of UGC Act, 1956

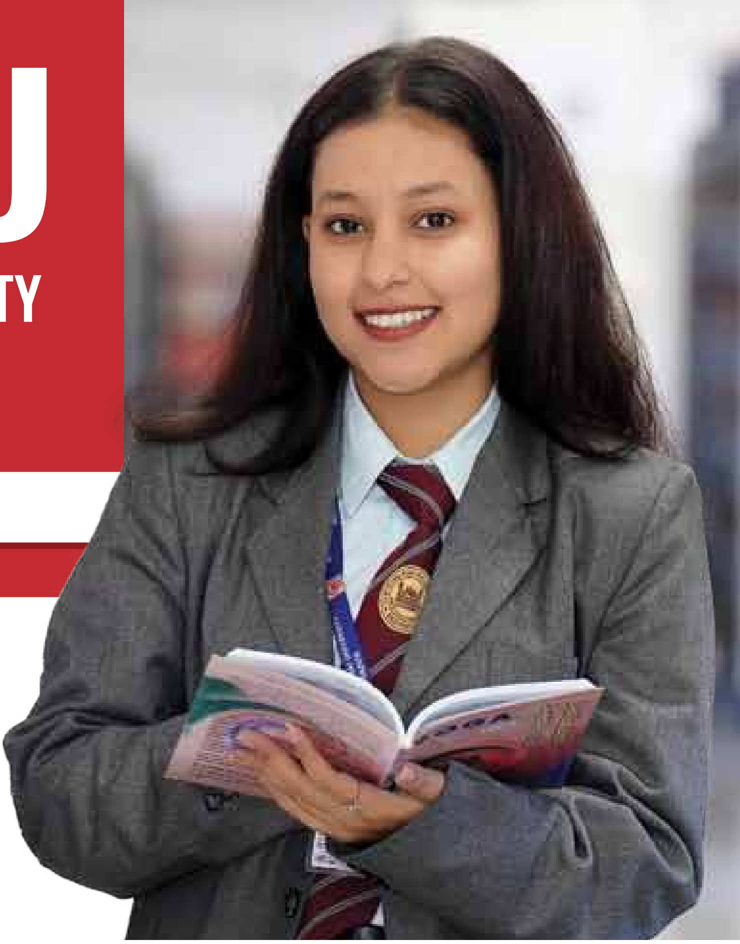

Legacy of Excellence Since 1952

PROUD TO BE ACCREDITED BY

ICAR — INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH

NABH

NABL

DSIR RECOGNIZED SIRO — DEPARTMENT OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH GOVT. OF INDIA

ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE IN

- Engineering & Technology
- Pharmaceutical Science
- Medical & Health Sciences
- Basic & Applied Sciences
- Paramedical & Allied Health Sciences
- Nursing
- Agricultural Sciences
- Yogic Science & Naturopathy
- Management & Commerce Studies
- Humanities & Social Sciences

100+ Laboratories

2000+ Research Publication

100+ Patents

70+ Years of Excellence

Offering **NCC & NSS**

1 Lakh+ Alumni

500+ Recruiters

125+ Courses

RANKED AMONG TOP UNIVERSITIES IN UTTARAKHAND

SCHOLARSHIP UPTO 100%

SCAN HERE TO REGISTER

1800-120-102-102 | admission@sgrru.ac.in | www.sgrru.ac.in | Patelnagar/Pathribagh, Dehradun

वर्ष 14 | अंक 37

दिव्य हिमगिरि

02-08 फरवरी, 2025

संपादक
कुँवर राज अस्थाना

वरिष्ठ संवाददाता
शंभूनाथ गौतम

ब्यूरो प्रमुख
मोनिका डबराल

विज्ञापन
पूनम आर्या

ग्राफिक डिजायनर
देव भट्ट

संवाददाता
हरिद्वार : डॉ. रजनीश गौतम
पौडी : रत्नमणि भट्ट
कोटद्वार : के.पी. बौंठियाल
रूद्रपुर : हेमचन्द्र बुडलाकोटी
चमोली : मुकेश रावत
रुड़की : श्रीगोपाल नारसन
नैनीताल : शीतल तिवारी
अल्मोड़ा : संजय कुमार अग्रवाल यएड.)
विकासनगर : अजय शर्मा
प्रसार : रमेश सिंह रावत

संपादकीय कार्यालय : 6, म्युनिसिपल रोड, बाला हिसार स्कूल के सामने, डालनवाला देहरादून यउत्तराखंड)
मोबाइल : +91 8433456398, 9410353164
Email: divyahimgiriddnègmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक कुँवर बहादुर अस्थाना द्वारा सरस्वती प्रेस, 2, ग्रीन पार्क, निरंजनपुर, देहरादून से मुद्रित तथा 39ध्7 ई, ई. सी. रोड, यनिकट मार्शल स्कूल सीनियर विंग) देहरादून-248001 उत्तराखण्ड से प्रकाशित।
संपादक: कुँवर बहादुर अस्थाना*

*यपीआरबी एक्ट के तहत प्रकाशित सामग्री के लिए उत्तरदायी)

बाहुबल के नाम पर अपराधी बनते हैं सफेदपोश

राजनीति में बाहुबलियों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग लंबे समय से की जाती रही है। इसे लेकर कुछ मौकों पर कड़े कदम भी उठाने के प्रयास हुए। मगर हकीकत यही है कि हर चुनाव के बाद संसद और विधानसभाओं में आपराधिक छवि के सदस्यों की संख्या कुछ बढ़ी हुई ही दर्ज होती है। निर्वाचन आयोग ने चुनावी पर्चा भरते वक्त प्रत्याशियों से अपनी संपत्ति के साथ-साथ आपराधिक मामलों का ब्योरा भी देने का प्रावधान बनाया। इससे लगा था कि राजनीति में आपराधिक छवि वाले लोगों की पैठ रुक जाएगी। मगर वह नियम बहुत कारगर साबित नहीं हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर कोई राजनीतिक दल ऐसी छवि वाले किसी व्यक्ति को चुनाव मैदान में उतारती है, तो उसे बताना होगा कि उसने उसे ही क्यों चुना, क्या उसके पास उससे बेहतर कोई प्रत्याशी नहीं था। मगर यह नियम भी बहुत बाध्यकारी साबित नहीं हुआ। इसका नतीजा है कि न केवल बाहुबली बहुत आसानी से राजनीति में प्रवेश पा जाते हैं, बल्कि चुनाव जीतने के बाद भी अपने बाहुबल का प्रदर्शन करने से गुरेज नहीं करते। उत्तराखंड में हरिद्वार की खानपुर सीट से वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक के बीच हुई गोलीबारी इसका ताजा उदाहरण है। बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक के बीच कुछ समय से सोशल मीडिया पर तीखी नोक-झोंक चल रही थी। यह तल्खी इतनी बढ़ी कि मौजूदा विधायक हथियारबंद होकर पूर्व विधायक के घर पहुंच गए और उनके परिजनों को धमकाया। इसकी प्रतिक्रिया में पूर्व विधायक भी हथियार लेकर सदलबल मौजूदा विधायक के दफ्तर पहुंचे और न केवल उन्हें अपशब्द कहे और ललकारा, बल्कि गोलियां भी दागीं। उसकी तस्वीरें खुद उन्होंने सोशल मीडिया पर भी डालीं। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस ने पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर लिया है और वर्तमान विधायक के खिलाफ भी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। पूर्व विधायक सत्तारूढ़ दल के हैं और वर्तमान विधायक निर्दलीय। यह भी बताया जा रहा है कि करीब पांच साल पहले भी पूर्व विधायक ने ऐसी अशोभन हरकत और गाली-गलौज की भाषा का इस्तेमाल किया था। उसके बाद पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया था। मगर बाद में उन्हें फिर पार्टी में जगह दे दी गई। ताजा घटना इसलिए चिंता का विषय है कि जब जनप्रतिनिधि खुद सोशल मीडिया पर इस कदर तल्ख टिप्पणियां करते हैं कि उससे गोली चलाने जैसी उत्तेजना पैदा हो जाती है, तो वे किसी गंभीर समस्या को सुलझाने में कितने संतुलित व्यवहार कर पाते होंगे। राजनेता का आचरण बहुत मायने रखता है। उसके व्यवहार का अनुकरण उसके समर्थक भी करते हैं। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि दोनों विधायकों के नीचे की कतार के नेताओं, कार्यकर्ताओं पर क्या असर पड़ा होगा। वे भी कभी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी। अक्सर सत्तापक्ष के नेता इस भरोसे के साथ हिंसक व्यवहार करने से नहीं हिचकते कि कानून के शिकंजे से वे आसानी से निकल जाएंगे। चुने हुए प्रतिनिधि के आत्मविश्वास का तो अनुमान लगाया जा सकता है। कानून इस मामले में कितनी सख्ती बरत पाएगा, दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि रसूखदार लोगों के मामले में पुलिस का रवैया कोई उत्साहजनक नहीं देखा जाता। मगर इस घटना के बाद राजनीतिक दलों से एक बार फिर यह स्वाभाविक अपेक्षा की जाती है कि वे अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को अनुशासित करने का प्रयास करेंगे।

कुँवर राज अस्थाना

बेहतर इंतजामों के बावजूद महाकुंभ में लग गया 'हादसों का ग्रहण'

महाकुंभ के चलते प्रयाग नगरी आस्था में डूबी हुई है। अध्यात्म, संस्कृति और आस्था का महासंगम महाकुंभ एक ऐसा अनुभव है जो हर बार नए रंग, नई अनुभूतियों और नई समझ के द्वार खोलता है। विश्व के सबसे विराट मानव समागम के सुरक्षित आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई महीनों से तैयारियों में लगे हुए थे। मुख्यमंत्री योगी ने मेला क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन के लिए अपने सबसे अनुभवी और योग्य अफसरों की ड्यूटी भी लगाई। लेकिन 29 जनवरी मौनी अमावस्या पर यूपी सरकार के बेहतर प्रबंधन के बावजूद हादसों का ग्रहण लग गया। भगदड़ करने से 30 से 40 लोगों की जान चली गई। सैकड़ों लोग घायल हैं। हालांकि विपक्ष मरने वालों की संख्या ज्यादा होने का दावा कर रहा है। महाकुंभ में हुई भगदड़ से मौत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी सबक बन गई। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षियों ने महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ देश और दुनिया भर सुर्खियों में है। 144 साल बाद आए इस महाकुंभ में हर कोई आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। देश के कोने-कोने से करोड़ों श्रद्धालु संगम नगरी में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। यूपी सरकार के मुताबिक महाकुंभ में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमान है। यह संख्या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की कुल आबादी से भी ज्यादा है। महाकुंभ के चलते प्रयाग नगरी आस्था में डूबी हुई है। अध्यात्म, संस्कृति और आस्था का महासंगम महाकुंभ एक ऐसा अनुभव है जो हर बार नए रंग, नई अनुभूतियों और नई समझ के द्वार खोलता है। संगमनगरी में दूर-दूर तक विस्तृत क्षेत्र, साधु-संतों के अखाड़े, श्रद्धालुओं की अपार भीड़, गंगा के किनारे विशाल तंबू नगरी और चारों ओर गूंजते मंत्रोच्चार ने एक दिव्य वातावरण बना रखा है। लेकिन एक हादसा सारे इंतजामों पर भारी पड़ जाता है। विश्व के सबसे विराट मानव समागम के सुरक्षित आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई महीनों से तैयारियों में लगे हुए थे। मुख्यमंत्री योगी ने मेला क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन के लिए अपने सबसे अनुभवी और योग्य अफसरों की ड्यूटी भी लगाई। 28 जनवरी तक सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। यूपी के मुख्यमंत्री वैसे भी अपने कठोर व्यवस्थाओं के लिए पूरे देश भर में जाने जाते हैं। लेकिन 29 जनवरी मौनी अमावस्या पर यूपी सरकार के बेहतर प्रबंधन के बावजूद हादसों का ग्रहण लग गया। महाकुंभ में भगदड़ करने से कम से कम 30 से 40 लोगों की जान

कुंभ में पहले भी कई बार भगदड़ मचने से सैकड़ों लोगों की जान गई

प्रयागराज के महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हुआ हादसा कोई पहल नहीं है। इससे पहले भी कुंभ में कई बार भगदड़ मचने से हादसे हो चुके हैं। देश में कुंभ और धार्मिक स्थलों में कई बार ऐसा हुआ है भगदड़ मचने से सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी है। इस बार प्रयागराज में हुए महाकुंभ के दौरान हादसे ने पुराने जख्मों की याद दिला दी। साल 1954 में जब आजादी के बाद प्रयागराज में स्वतंत्र भारत का पहला कुंभ आयोजित हुआ तो लाखों लोग उमड़ पड़े। इस दौरान भगदड़ हो गई इसमें 800 लोग कुचलकर मर गए। साल 1954 का कुंभ मेला भारत की आजादी के बाद पहला मेला था। इसको एक त्रासदी के तौर पर भी याद किया जाता है। 3 फरवरी 1954 को इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में कुंभ मेले में मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर पवित्र स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची थी। उस वक्त भगदड़ मच गई। इसमें लगभग 800 लोगों की मौत हो गई थी। दुर्घटना की फोटो उस समय एक बड़े अखबार के छायाकार ने अपनी जान की परवाह न कर फोटो खींची थी और फिर सचित्र समाचार प्रकाशित होने पर सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। उस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। उसके बाद साल 1986 में कुंभ मेले में एक भगदड़ मच गई थी। इसमें कम से कम 200 लोगों की जान चली गई। यह हालात जब पैदा हुए जब तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सांसदों के साथ हरिद्वार पहुंचे। जब सुरक्षाकर्मियों ने आम लोगों को नदी के किनारे जाने से रोक दिया, तो भीड़ बेकाबू हो गई है और भगदड़ मच गई। इसी तरह की एक त्रासदी साल 2003 में भी देखने को मिली थी। 2003 में मुंबई के नासिक में उस समय भगदड़ मच गई जब कुंभ मेले के दौरान पवित्र स्नान के लिए गोदावरी नदी में हजारों श्रद्धालु इकट्ठा हुए। भगदड़ में महिलाओं समेत कम से कम 39 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। साल 2013 में उत्तर प्रदेश के कुंभ मेले में 10 फरवरी 2013 को इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर एक फुटब्रिज के ढह जाने से भगदड़ मच गई। इसमें भी 42 लोगों की जान चली गई और 45 लोग घायल हो गए थे।

चली गई। सैकड़ों लोग घायल हैं। हालांकि विपक्ष मरने वालों की संख्या ज्यादा होने का दावा कर रहा है। महाकुंभ में हुई भगदड़ से मौत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी सबक बन गई। इसके साथ अभी तक कुंभ के मेला क्षेत्र में दो बार आग लगने से कई टेंट जलकर राख हो गए हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षियों ने महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। हालांकि उसी दिन योगी ने कुंभ में मारे गए लोगों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए देने का एलान कर दिया। लेकिन महाकुंभ में भगदड़ सीएम योगी की कठोर सुरक्षा व्यवस्था पर दाग लगा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कई बार टेलीफोन करके पूरी जानकारी ली। इसके बाद योगी सरकार ने कुंभ में कई कुशल प्रबंधन में माहिर पुलिस ऑफीसरों को ड्यूटी पर भेजा। सीएम योगी के आदेश पर कुंभ की सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए दूसरे जिलों के 7 आईपीएस महाकुंभ भेजे गए हैं। इनमें देवरिया के एसपी दीपेंद्र नाथ चौधरी, भ्रष्टाचार निवारण संगठन में जिम्मेदारी संभाल रहे लक्ष्मीनिवास मिश्र, राजधारी चौरसिया, डीसीपी कानपुर श्रवण कुमार सिंह हैं। वहीं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विकास चंद्र त्रिपाठी, एएसपी बस्ती ओमप्रकाश सिंह, एएसपी श्रावस्ती प्रवीण कुमार यादव शामिल हैं। इससे पहले कुंभ-2019 के 2 अफसरों को भेजा था महाकुंभ में भगदड़ के बाद सीएम योगी ने गुरुवार को अपने दो भरोसेमंद अफसर को प्रयागराज भेजा था। आईएएस आशीष गोयल और भानु चंद्र गोस्वामी को तत्काल प्रयागराज पहुंचने को कहा गया। 2019 अर्ध कुंभ गोयल और गोस्वामी की जोड़ी ने विजय किरण के साथ मिलकर करवाया था। भानु तब डीएम और प्राधिकरण के वीसी थे। आशीष गोयल तब के इलाहाबाद के कमिश्नर और अर्धकुंभ मेला के प्रभारी थे। पांच और विशेष सचिव रैंक के अधिकारियों को कुंभ भेजा गया है, जिनका अनुभव रहा है। हालांकि पुलिस विभाग में अभी किसी को कुंभ जाने को नहीं कहा गया। इन दोनों अफसरों के अलावा फ्रुल्ल त्रिपाठी, प्रतिपाल चौहान और आशुतोष दुबे समेत 5 अनुभवी पीसीएस अफसरों को भी महाकुंभ भेजा गया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर करारा हमला बोला समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ में भगदड़ के लिए केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है। अखिलेश ने गुरुवार

को कहा कि महाकुंभ में भगदड़ की जो घटना हुई वह दुखद है, उसे नहीं होना चाहिए था लेकिन एक बात साफ है कि सरकार ने जितना प्रचार किया था, उतना इंतजाम उसने नहीं किया। अगर इंतजाम हुआ होता तो शायद इतने लोगों की मौत नहीं हुई होती। सपा नेता ने कहा कि महाकुंभ के आयोजन में केंद्र सरकार ने कितना सहयोग दिया, इसका ब्यौरा उसे देना चाहिए। अखिलेश ने महाकुंभ के लिए वीआईपी निमंत्रण पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह पहली बार हुआ है जब महाकुंभ के लिए सरकार ने वीआईपी लोगों को न्योता दिया। उन्हें कार्ड भेजकर बुलाया। अब तक ऐसा नहीं होता था। लोग आस्था की वजह से कुंभ में आते हैं, उन्हें बुलाया नहीं जाता। सपा अध्यक्ष ने कहा कि अभी भी बहुत लोग लापता हैं। सरकार को मृतकों एवं लापता लोगों की सूची जारी करनी चाहिए। उन्होंने 25 लाख रुपए के मुआवजे को अपर्याप्त बताया। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने भी खराब इंतजाम पर यूपी सरकार पर सवाल उठाए।

हादसे के बाद सीएम योगी न महाकुंभ में वीआईपी कल्चर खत्म किया

महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े फैसले लिए। अब अगले महीने 26 फरवरी तक महाकुंभ में कोई भी वीआईपी नहीं रहेगा। चाहे आम हो या खास, संगम में स्नान करने आएगा एक समान नजर आएगा। हालांकि यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुछ दिन पहले ले लेना चाहिए लेकिन देर आए दुरुस्त आए। पिछले कई दिनों से महाकुंभ में स्नान करने आए वीआईपी लोगों खास सुविधा देने पर नाराजगी भी देखी गई थी। बुधवार को महाकुंभ में हुए हादसे के बाद योगी सरकार ने कई बदलाव किए हैं। सीएम योगी ने महाकुंभ मेले में मची भगदड़ के बाद पांच मुख्य बदलाव किए हैं। महाकुंभ नगर को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है यानि किसी भी तरह के वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। जिन्हें प्रशासन ने लागू कर दिया है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में सभी प्रकार के वाहनों को सख्त वर्जित कर दिया गया है और पूरी तरह से नो-व्हीकल जोन में तब्दील कर दिया गया है। मेला क्षेत्र में वीवीआईपी पास को रद्द कर दिया गया है। किसी भी स्पेशल पास वाहनों को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुचारू बनाने के लिए एकतरफा यातायात व्यवस्था लागू की गई है। शहर में भीड़भाड़ को कम करने के लिए पड़ोसी जिलों से आने वाले वाहनों को जिले की सीमाओं पर ही रोका जा रहा है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए 4 फरवरी तक शहर में चार पहिया वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। त्रासदी के बाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और अंतर-विभागीय समन्वय पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) द्वारा महाकुंभ व्यवस्थाओं की समीक्षा करने का आदेश दिया। एडीजी और प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट को शहर से सभी भक्तों की सुरक्षित और सुचारू विदाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। सीएम योगी ने रेल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। परिवहन निगम को भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कहीं भी भीड़ का दबाव नहीं बढ़ना चाहिए और सड़कों पर यातायात या लोगों की भीड़ नहीं होनी चाहिए। सड़कों पर कब्जा जमाए बैठे रेहड़ी-पटरी वालों को यातायात में व्यवधान को रोकने के लिए खाली जगहों पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

केंद्रीय बजट 'विकासोन्मुखी और जनकल्याणकारी': सीएम धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सालाना 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त करते हुए देश के मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकासोन्मुखी और जनकल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शानदार और संतुलित बजट के लिए बधाई देते हुए कहा कि केंद्रीय बजट से, उत्तराखंड को कई योजनाओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ होगा। शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस वर्ष के संशोधित अनुमान में केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा लगभग 14387 रुपए करोड होगा। इससे मौजूदा वित्तीय वर्ष में प्रदेश को 444 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलने का रास्ता साफ हो गया है। आगामी वर्ष हेतु यह राशि लगभग 15902 करोड़ रुपए तक जा सकती है। राज्य के लिए यह राशि अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बजट-पूर्व सम्मेलन में 11 बिन्दुओं का निवेदन किया था। जिसका समावेश भी बजट में दिख रहा है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से अपने राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस व साइबर सुरक्षा से संबंधित उकृष्टता केन्द्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) स्थापित किये जाने का निवेदन किया था। इस बजट में देश में 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सिलेंस एवं सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाने की घोषणा की गई है। इसी तरह सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की घोषणा प्रदेश के लिए भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। नॉलेज इकॉनोमी के लिए यह एक मजबूत नींव होगी। इसी तरह केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने की समय-सीमा 2028 तक बढ़ाने के लिए राज्य का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय बजट में राज्यों के पूंजीगत विकास के लिए 1.5 लाख करोड रुपए कर्ज का प्रावधान किया गया है। यह इस वर्ष के संशोधित अनुमान 1,25,000 करोड से 25,000 करोड़ रुपए अधिक है। विगत दो वर्षों में इस ब्याजमुक्त योजना से हमारे राज्य को बड़ा लाभ मिला है।

जिलों में होगा कैंसर मरीजों का उपचार

मुख्यमंत्री ने कहा कि 125 शहरों के लिए नई उडान योजना शुरु किए जाने का लाभ उत्तराखण्ड को भी मिलेगा। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर सेंटर बनाए जाने से प्रदेश में चिकित्सा सेवा को विस्तार मिलेगा। देश के 100 जिलों में धन धान्य योजना की शुरुआत से प्रदेश के किसान के भी लाभान्वित होने की आशा है। इसी तरह किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किये जाने की घोषणा से प्रदेश के किसानों को भी फायदा होगा।

मिडिल क्लास पर मेहरबान बजट, 12 लाख की कमाई पर टैक्स की टेंशन खत्म

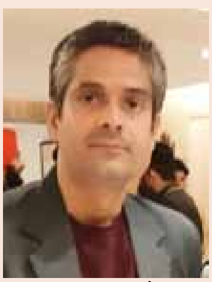

शंभू नाथ गौतम
वरिष्ठ पत्रकार

एक फरवरी शनिवार को मोदी सरकार ने बजट का पिटारा खोला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार के बजट में मिडिल क्लास पर मेहरबान हो गई। उनकी सारी मुरादें पूरी कर दी हैं। मिडिल क्लास के लोगों को उम्मीद से दो गुना नहीं बल्कि चार गुना एलान कर दिया। मध्यवर्गीय के लोगों को केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स में इतनी बड़ी छूट दे दी है कि अब वह आराम से पैसे की बचत भी कर सकेंगे। इस बजट में मोदी सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को सीधा संदेश दिया कि 12 लाख रुपए तक सालाना कमाओ और ''टैक्स का टेंशन'' खत्म करो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किए गए बजट में इनकम टैक्स छूट को बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया, जो कि पहले 7 लाख रुपये थी। सरकार के इस एलान के बाद अब एक लाख रुपये प्रति महीने कमाने वाले व्यक्ति को टैक्स नहीं देना होगा। बजट में मोदी सरकार ने कई नई योजनाओं की घोषणा की। सरकार की ओर घोषित की गई साल 2025 की नई योजनाओं को मुख्य फोकस किसानों और महिलाओं पर रहा। बजट में बिहार भी खूब मालामाल हुआ।

इस बार मोदी सरकार ने बजट में मध्यम वर्ग के आयकर दाताओं को पुरानी मांग पूरी कर दी। हर साल केंद्रीय बजट में मिडिल क्लास के लोगों की निगाहें इनकम टैक्स में छूट कितनी मिलेगी, लगी रहती है। आखिरकार 1 फरवरी साल 2025 दिन शनिवार को मध्यम वर्ग लोगों के लिए अच्छी खबर आ गई। शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पेश किए गए बजट में कई बड़े एलान किए गए। लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण इस बार टैक्स में दी गई बंपर छूट रही। कुल मिलाकर केंद्र सरकार इनकम टैक्स में छूट देने को लेकर मेहरबान रही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार के बजट में मिडिल क्लास को खुश कर दिया। उनकी सारी मुरादें पूरी कर दी हैं। मिडिल क्लास के लोगों को उम्मीद से दो गुना नहीं बल्कि चार गुना एलान कर दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास के लिए खजाना खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मध्यवर्गीय के लोगों को केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स में इतनी बड़ी छूट दे दी है कि अब वह आराम से पैसे की बचत भी कर सकेंगे। इस बजट में मोदी सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को सीधा संदेश दिया कि 12 लाख रुपए तक सालाना कमाओ और ''टैक्स का टेंशन'' खत्म करो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को पेश किए गए बजट में इनकम टैक्स छूट को बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया, जो कि पहले 7 लाख रुपये थी। सरकार के इस एलान के बाद अब एक लाख रुपये प्रति महीने कमाने वाले व्यक्ति को टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने एलान किया है कि न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। निर्मला सीतारमण ने ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया है। वित्त मंत्री के इस एलान के साथ अब वेतन पाने वाले लोगों को 12.75 लाख रुपये तक (स्टैंडर्ड डिडक्शन) की आय पर टैक्स नहीं देना है। सरकार द्वारा वेतनभोगी लोगों को 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन की कटौती दी जाती है। अब नौकरीपेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना 12.75 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। दूसरे और तीसरे स्लैब के टैक्स सरकार 87ए के तहत माफ कर देगी। इसके अलावा 75 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। इस तरह नौकरीपेशा लोगों की कुल 12.75 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि राहत

केवल नौकरीपेशा लोगों के लिए है। अन्य किसी भी जरिए से आमदनी होने पर टैक्स में छूट की सीमा केवल 12 लाख रुपए ही रहेगी। साथ ही अब सभी टैक्सपेयर्स पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेंगे। इससे पहले तक यह लिमिट 2 साल थी। वहीं सीनियर सिटीजंस के लिए टीडीएस की सीमा 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पेश किए गए बजट के बाद आयकर में दी गई राहत के बाद नौकरीपेशा वाले लोग गुणा-भाग करने में लग गए हैं। बजट भाषण की शुरुआत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने 'ज्ञान' से की। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस 'जीवाईएएन' पर यानि गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी पर होगा। 10 साल में हमने बहुमुखी विकास किया है और आगे भी हम इसे जारी रखेंगे। उन्होंने कहा, यह बजट सरकार की विकास को बढ़ाने, सभी के डेवलपमेंट, मिडिल क्लास की क्षमता को बढ़ाने के लिए समर्पित है। हमने इस सदी के 25 साल पूरा करने जा रहे हैं। हमारी विकसित भारत की उम्मीदों ने हमें प्रेरणा दी है। हमारी अर्थव्यवस्था सभी बड़ी इकोनमी में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। इसके साथ ही नए इनकम टैक्स बिल का एलान भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। उन्होंने कहा न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एफडीआई की सीमा बढ़ाने जा रहे हैं। सरकार ने 7 टैरिफ रेट को हटाने का फैसला किया है। 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके साथ सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का एलान किया। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले फाइनेंशियल इयर में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे। सरकार का फोकस बिहार पर भी दिखा, जहां इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। सीतारमण ने बिहार के लिए नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना करने का ऐलान किया। राज्य में आईआईटी का विस्तार होगा। मखाना बोर्ड और 3 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के रूप में संसद में लगातार आठवीं बार बजट पेश किया। यह बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। सरकार द्वारा इस बजट में हेल्थ से लेकर कृषि क्षेत्रों तक में कई बड़े बदलावों की घोषणा की गई हैं। वहीं आम लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए भी सरकार ने पूरे प्रयास किया है। बजट में बहुत सी चीजों को सस्ता किया गया है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा राहत मिली है। बजट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने इस बजट की सराहना की और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि ये आम आदमी का बजट है। उन्होंने कहा कि सभी आय वर्ग के लोगों को इससे फायदा हुआ है। इस बजट से आत्मनिर्भर भारत के सपने को नई गति मिलेगी। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बजट पर सरकार को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये बजट मध्यम वर्ग के लिए बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी और सशक्त नेतृत्व में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय बजट 2025-26 के अंतर्गत 12 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

नई टैक्स रिजीम के तहत 0-4 लाख रुपये की आय पर टैक्स शून्य होगा

वित्त मंत्री ने कहा कि नई टैक्स रिजीम के तहत 0-4 लाख रुपये की आय पर टैक्स शून्य होगा। वहीं, 4-8 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत, 8-12 लाख रुपये की आय पर 10 प्रतिशत, 12-16 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत, 16-20 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत, 20-24 लाख रुपये की आय पर 25 प्रतिशत और 24 लाख से अधिक की आय पर टैक्स की दर 30 प्रतिशत होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई टैक्स रिजीम के तहत किए गए इस बदलाव के बाद 12 लाख रुपये की आय पर 80,000 रुपये की बचत होगी। वहीं, 18 लाख रुपये की आय पर 70,000 रुपये, 25 लाख रुपये की आय पर 1,10,000 रुपये की बचत होगी। बता दें कि बजट पेश किए जाने से पहले ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि सरकार नई टैक्स रिजीम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहती है, इनकम ढांचे में फिलहाल संभावित बदलाव की भी बात की जा रही थी। कहा जा रहा था कि नए स्लैब के तहत टैक्स दरों में कुछ संशोधन किए जाने की भी उम्मीद है। ऐसा हुआ तो करदाताओं पर टैक्स का बोझ कम होगा और लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे बचेंगे। हालांकि ये बदलाव न्यू टैक्स रिजीम में किया गया है। ओल्ड टैक्स रिजीम में बदलाव नहीं हुआ है।

बजट में नई योजनाओं के साथ मुख्य फोकस किसान और महिलाओं पर रहा

बजट में मोदी सरकार ने कई नई योजनाओं की घोषणा की है। मोदी सरकार की ओर घोषित की गई साल 2025 की नई योजनाओं को मुख्य फोकस किसान और महिला हैं। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार पहली बार उद्यम शुरू करने वाली पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए दो करोड़ रुपये का ऋण शुरू करेगी। वित्त मंत्री ने 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए यह भी कहा कि एसएमई और बड़े उद्योगों के लिए एक विनिर्माण मिशन स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा सरकार श्रम-प्रधान क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सुविधाजनक उपाय करेगी। उन्होंने कहा कि ऋण गारंटी 'कवर' को दोगुना करके 20 करोड़ रुपये किया जाएगा तथा गारंटी शुल्क को घटाकर एक प्रतिशत किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार पहली बार उद्यम शुरू करने वाली पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए दो करोड़ रुपये का ऋण शुरू करेगी। वित्त मंत्री ने 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए यह भी कहा कि एसएमई और बड़े उद्योगों के लिए एक विनिर्माण मिशन स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा सरकार श्रम-प्रधान क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सुविधाजनक उपाय करेगी। उन्होंने कहा कि ऋण गारंटी 'कवर' को दोगुना करके 20 करोड़ रुपये किया जाएगा तथा गारंटी शुल्क को घटाकर एक प्रतिशत किया जाएगा। वहीं वित्त मंत्री ने बजट की शुरुआत में ही किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। सरकार ने किसानों के लिए धन धान्य योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कम पैदावार, आधुनिक फसल गहनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिले शामिल किए जाएंगे, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होने वाला है। इस बजट में सरकार ने किसानों को खुश करते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। ऐसे में अब किसान किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 5 लाख तक की लोन ले सकते हैं। सरकार के इस फैसले से किसानों को काफी फायदा होने वाला है। बजट में सरकार ने किसानों के लिए और भी कई बड़े ऐलान किए हैं। इसमें जन धान्य योजना की घोषणा, कृषि कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों की मदद, कम उत्पादकता वाले 100 जिलों को कवर करने के लिए ख्रषि योजना शामिल है। किसान

क्रेडिट कार्ड योजना सरकार द्वारा साल 1998 में शुरू की गई थी। इस योजना के माध्यम में सरकार द्वारा किसानों को लोन दिया जाता है। लोन की रकम का इस्तेमाल किसान खेती करने में कर सकते हैं। योजना की खास बात यह है कि इस योजना के तहत किसानों को काफी कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है, जिससे किसानों पर वित्तीय बोझ भी नहीं आता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को 9 प्रतिशत की ब्याज दर पर खेती के लिए लोन दिया जाता है। वहीं साथ में 2 प्रतिशत की सब्सिडी भी दी जाती है। इसक अलावा कर्ज समय से कर्ज चुकाने पर ब्याज दर में 3 प्रतिशत की कटौती भी की जाती है। ऐसे में किसान इस योजना के तहत केवल 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर लोन ले सकते हैं।

मोदी सरकार ने 36 जीवन रक्षक दावों को कस्टम डड्यूटी से हटाया

बजट में इस बार सरकार ने 36 जीवनरक्षक दवाओं से कस्टम डड्यूटी हटा दी है। इससे ये दवाएं सस्ती होंगी। वहीं, ड्यूटी घटने से आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी), एलसीडी-एलईडी टीवी और मोबाइल फोन भी सस्ते हो सकते हैं। उधर, सरकार ने इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% कर दी है, जिससे ये महंगा होगा। हालांकि ये प्रोडक्ट कितने सस्ते या महंगे होंगे, ये तय नहीं है। सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देशभर में जीएसटी लागू किया था, जिसके बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी बढ़ाई-घटाई जाती है। ड्यूटी के बढ़ने और घटने का इनडायरेक्ट असर चीजों की कीमतों पर पड़ता है। उल्लेखनीय है कि बजट में कोई भी प्रोडक्ट सीधे तौर पर सस्ता-महंगा नहीं होता। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज डड्यूटी जैसे इनडायरेक्ट टैक्स के घटने-बढ़ने से चीजें सस्ती-महंगी होती है। ड्यूटी के बढ़ने और घटने का इनडायरेक्ट असर चीजों की कीमतों पर पड़ता है। मान लीजिए, सरकार ने बजट में एलान किया कि वो गोल्ड पर इम्पोर्ट ड्यूटी में 10% की कटौती कर रही है। इसका असर ये होगा कि विदेश से सोना मंगाना 10% सस्ता हो जाएगा। यानी, सोने की ज्वेलरी, बिस्किट, सिक्के की कीमतें कम हो जाएगी। बजट 2025 में कौन कौन से सामान महंगे हुए हैं, इसे लेकर इस बजट में वित्त मंत्री द्वारा कोई भी घोषणा नहीं की गई हैं। ऐसे में इस बजट 2025 से आम लोगों को काफी राहत मिली है। सरकार ने इस बजट में बहुत सी चीजों को सस्ता कर दिया है, जिससे मिडिल क्लास लोगों को काफी फायदा होगा। 82 सामानों पर से इस बजट में टैक्स को हटाया गया है। इसके अलावा बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की क सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया। सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना बढ़ाया जाएगा। साथ ही कहा कि सरकार पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये की सीमा वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड पेश करेगी। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि 2047 तक 100 गीगावाट की न्यूक्लिर एनर्जी क्षमता विकसित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ स्मॉल मॉडयूरल रिएक्टर्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए न्यूक्लिर एनर्जी मिशन की स्थापना की जाएगी। 2033 तक पांच छोटे मॉडयूलर रिएक्टर चालू हो जाएंगे। बजट में वित्त मंत्री द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे किसानों को सस्ता लोन पाने में मदद मिलेगी।

केंद्र सरकार ने बजट में बिहार के लिए खोला खजाना

राज्यों के हिसाब से देखें तो बजट 2025-26 में सबसे ज्यादा फायदा बिहार को हुआ है। बिहार के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री ने बिहार के लिए मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की जबकि राज्य में नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। इसके अलावा पटना आईआईटी और पटना एयरपोर्ट का भी विस्तार किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि मखाना के उत्पादन, विपण न और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। माना जा रहा है कि यह घोषणा बिहार के किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी और मखाना बोर्ड के गठन होने से किसानों को और भी लाभ हो सकते हैं। बिहार में फिलहाल लगभग 35 हजार हेक्टेयर में मखाने की खेती होती है। 25 हजार किसान इससे जुड़े हुए हैं। देश में सबसे अधिक मखाना उत्पादन करने वाला राज्य बिहार है। लगातार बाढ़ की विभीषिका झेलते रहने वाले बिहार के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिमी कोशी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की भी घोषणा की, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले बड़ी संख्या में किसानों को लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने बिहार में एयरपोर्ट सेवाओं में विस्तार करने की घोषणा की है। उड़ान स्कीम के तहत देश के 120 नए स्थानों को एयरसेवा से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बजट में पटना एयरपोर्ट की क्षमता में व्यापक विस्तार करने की घोषणा की तथा बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने का भी ऐलान किया। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने पटना स्थित आईआईटी का विस्तार करने का ऐलान किया। केंद्र सरकार के फैसले से बिहार के युवाओं को काफी सुविधा होगी। वहीं केंद्र सरकार ने बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना का फैसला लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 के बाद खोले 5 आईआईटी में अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। इससे 6500 और छात्रों को शिक्षा मिलेगी। हॉस्टल और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा।

राधा बहन का पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयन: एक प्रेरणादायक यात्रा

शीशपाल गुसाईं

भारतीय संस्कृति में समाज सेवा और त्याग के क्षेत्र में कई अद्वितीय व्यक्तियों ने अपनी छाप छोड़ी है। ऐसी ही एक प्रेरणादायक शख्सियत हैं राधा बहन, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। उनके चयन की घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की गई, जो न केवल उनके लिए, बल्कि समस्त उत्तराखण्ड के लिए गर्व की बात है। राधा बहन का जन्म 16 अक्टूबर 1933 को अल्मोड़ा जिले के धुरका गांव में हुआ था। उनके माता-पिता, कमलापति और रेवती भट्ट, ने उन्हें अपने समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। मात्र 18 वर्ष की आयु में, उन्होंने अपने घर से निकलकर समाज सेवा की दिशा में कदम बढ़ाया। यह एक साहसी निर्णय था, जिसने उनके भविष्य की दिशा तय की।

कौसानी में आकर राधा बहन ने बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से न केवल लड़कियों को जीवन जीने की कला सिखाई, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी कार्य किया। उनका यह प्रयास एक व्यापक सामाजिक बदलाव की नींव स्थापित करने में सहायक रहा। 1957 में भूदान आंदोलन के साथ उनकी पदयात्रा का आरंभ हुआ। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा स्थापित सिद्धांतों के आधार पर था, जिसमें भूमि की असमानता को समाप्त करने और गरीबों को भूमि प्रदान करने पर जोर दिया गया। राधा बहन ने बालिका शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, जल, जंगल, जमीन, ग्राम स्वराज, शराब आंदोलन और युवा महिला सशक्तीकरण जैसे विविध आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी की।

राधा बहन ने सरला बहन, जो महात्मा

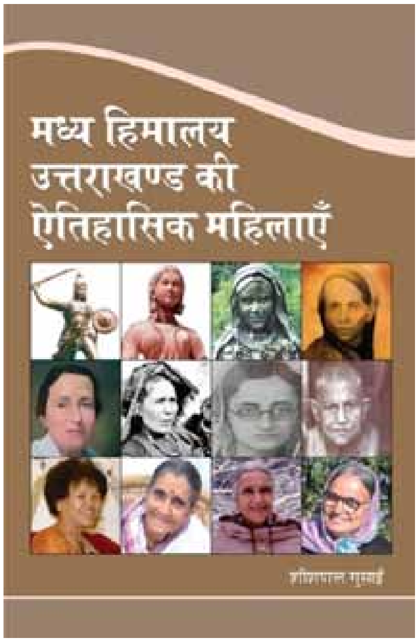

गांधी की अनुयायी थीं, के कार्यों से प्रेरणा ली। 1975 में, उन्होंने सरला बहन के 75वें जन्मदिवस पर एक पद यात्रा की शुरुआत की, जो उनके जीवन के समर्पण को दर्शाती है। यह यात्रा न केवल व्यक्तिगत समर्पण की प्रतीक थी बल्कि समाज में व्यापक बदलाव लाने के लिए किए गए उनके प्रयासों का भी संकेत थी। पद्मश्री पुरस्कार के लिए राधा बहन भट्ट का चयन उनकी अटूट मेहनत, समर्पण और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को समझने का परिणाम है। यह पुरस्कार उनके कार्यों को मान्यता और एक प्रेरणादायक संदेश देता है कि समाज सेवा की यात्रा किसी भी परिस्थिति में कभी भी शुरू की जा सकती है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि त्याग और सेवा के माध्यम से हम अपने समाज को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं।

वन संरक्षण और समाज सेवा में योगदान

राधा बहन का जीवन एक प्रेरणादायक यात्रा है, जिसमें उन्होंने वन संरक्षण, सामाजिक जागरूकता और ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए अपार संघर्ष किया है। 1976 में देवीधूरा ब्लॉक से निकली 75 दिनों की लंबी पदयात्रा उनके कार्यों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस यात्रा में उन्होंने 65 गांवों का दौरा किया, जहां उन्होंने वन संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के महत्व को उजागर किया। पदयात्रा के दौरान, राधा बहन ने 40 बालवाड़ी और 30 महिला संगठनों की स्थापना करके शिक्षा और स्वावलंबन के लिए एक ठोस आधार तैयार किया। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को संगठित किया, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें और अपने समुदाय की समस्याओं का सामना कर सकें। साथ ही, उन्होंने 12 गांवों के किसानों को कृषि के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर सतत विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ।

1980 में, राधा बहन ने खनन के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने बताया कि कैसे अनियंत्रित खनन से पर्यावरण और स्थानीय समुदायों को हानि पहुंचती है। इससे न केवल प्राकृतिक संसाधनों का रिक्तिकरण होता है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। उनका प्रयास यह था कि समाज को यह समझाया जा सके कि विकास के नाम पर यदि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया गया, तो वह अंततः मानवता के लिए विनाशकारी साबित होगा। 2006 से 2010 के बीच, राधा बहन ने हिमालय और नदियों का सर्वेक्षण करते हुए हाइड्रो पावर परियोजनाओं का विरोध किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन परियोजनाओं से पारिस्थितिकी तंत्र में गंभीर असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। उनका यह प्रयास वास्तविकता को सामने लाने के लिए ही नहीं, बल्कि जन जागरूकता फैलाने के लिए भी था।

राधा बहन को मिला 2024 का स्वामीराम मानवता पुरस्काररू 10 लाख रुपये की सम्मान राशि प्राप्त

13 नवंबर 2024 को हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट मेडिकल कॉलेज में 29वां महासमाधि दिवस, स्वामीराम की जीवनकृष्टि और उनके द्वारा स्थापित सेवा के सिद्धांतों को जीवित रखने का एक महत्वपूर्ण अवसर था। षि चौतन्य आश्रम, सोनीपत, हरियाणा की संस्थापक आनंदमूर्ति गुरु मां, डॉ विजय धस्माना द्वारा इस विशेष अवसर पर, 2024 वर्ष का स्वामीराम मानवता पुरस्कार

गांधीवादी नेता राधा बहन भट्ट को प्रदान किया गया। राधा बहन भट्ट, जिन्होंने पहाड़ी महिलाओं को सशक्त करने, शिक्षा के प्रचार, पर्यावरण संरक्षण, और शराब विरोधी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुरस्कार के अंतर्गत राधा बहन भट्ट को गोल्ड मेडल, प्रशस्ति पत्र और दस लाख रुपये का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया, जो कि उनके समर्पण और साहस का प्रतीक है। इस पुरस्कार ने न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों को मान्यता दी, बल्कि समाज में उनकी प्रेरणादायक भूमिका को भी उजागर किया। राधा बहन ने समाजसेवा के लिए कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जिनमें से कुछ उनके अनेकों कार्यों की प्रशंसा के रूप में हैं। कौसानी के लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी राधा बहन आज भी समाज सेवा में सक्रिय हैं, और उनका जीवन यह दर्शाता है कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपने समुदाय और पर्यावरण के लिए सकारात्मक बदलाव ला सकता है।

वर्ष 2024 में प्रकाशित मेरी पुस्तक 'मध्य हिमालय उत्तराखण्ड की ऐतिहासिक महिलाएँ' प्रथम संस्करण में, मैंने 31 अद्वितीय महिलाओं के जीवन का उल्लेख किया है, जिनमें एक प्रमुख नाम राधा बहन का है। राधा बहन जी का जीवन और कार्य केवल उत्तराखण्ड के लिए नहीं, बल्कि सम्पूर्ण भारतीय समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं।

राधा बहन का चयन पद्मश्री पुरस्कार के लिए आदर्श और प्रशंसनीय है। उनका संपूर्ण जीवन नवाचारी दृष्टिकोण और समाज सेवा के प्रति समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने न केवल अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं, बल्कि उन्होंने अपनी अखंड निष्ठा और साहस से अपने समाज में भी बदलाव लाने का प्रयास किया है। मेरी पुस्तक में राधा बहन की जीवनी का विस्तृत उल्लेख करके, मैंने उनके संघर्ष, उपलब्धियों और समर्पण को दर्शाने का प्रयास किया है। यह न केवल उनके कार्यों की प्रशंसा है, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा भी है जो समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रयासरत हैं।

राधा बहन को इस सम्मानित पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई देना मेरे लिए गर्व का विषय है। उनका यह चुनाव यह दर्शाता है कि समाज में महिलाओं की भूमिका और उनके कार्यों की महत्ता को पहचाना जा रहा है। इससे नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी कि वे भी अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करें।

प्रयागराज महाकुंभ में लगे उत्तराखंड पवेलियन में पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज

'बड़ी मात्रा में उत्तराखंड के उत्पादों को पसंद कर रहे हैं लोग, सात लाख से अधिक लोग पहुंच चुके हैं उत्तराखंड पवेलियन में'- *महाराज*

प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने प्रयागराज महाकुंभ-2025 में लगे उत्तराखंड पवेलियन में पहुंच कर प्रदेश के विभिन्न स्टॉलों का निरिक्षण किया।

प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने बुधवार को प्रयागराज महाकुंभ-2025 में लगे उत्तराखंड पवेलियन में पहुंच कर प्रदेश के विभिन्न स्टॉलों का निरिक्षण किया। उन्होंने कहा कि यहां पर उत्तराखंड के अंतरराष्ट्रीय ब्रांड 'हाउस ऑफ हिमालया' के स्टॉल पर बहुत से उत्पाद रखे गए हैं जिन्हें बड़ी संख्या में लोग पसंद कर रहे हैं। उत्तराखंड के सभी उत्पादों के प्रति यहां लोगों में काफी रुचि देखने को मिल रही है।

पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री श्री महाराज ने बताया कि उत्तराखंड पवेलियन में लगे प्रदेश के विभिन्न स्टॉलों में अब तक सात लाख से भी अधिक लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं। पवेलियन में बने पर्यटन विकास परिषद, श्री बद्री-केदार द्वारा, मानसखंड मंदिर मिशन के अंतर्गत विभिन्न सिद्ध पीठों सहित दिव्य मंदिरों की प्रतिकृतियां और जल जीवन मिशन के स्टॉल श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ-2025 मात्र एक मेले का ही आयोजन नहीं बल्कि यह भारत और विश्व की तमाम संस्कृतियों के मिलन का एक प्रमुख केन्द्र भी है, जिसमें देश-विदेश के तीर्थ यात्री अपनी आध्यात्मिक शुद्धि के लिए यहां एकत्रित होते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में स्थापित उत्तराखंड पवेलियन में स्थित विभिन्न स्टॉलों में जहां एक ओर देवभूमि के उत्पाद शॉल, बिच्छू घास से बनी वस्तुएं और अन्य उत्पादों को बड़ी मात्रा में लोग पसंद कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर देश-विदेश से बड़ी संख्या में आये लोग यहां उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति का सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए लुफ्त उठा रहे हैं।

उपलब्धियां और अतुलनीय फैसलों से सीएम धामी के हौसले बुलंद

वर्ष 2025 उत्तराखंड के लिए कई ऐतिहासिक उपलब्धियों का साल होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ऐतिहासिक और अतुलनीय फैसलों से उत्तराखंड तेजी के साथ विकास के विजयपथ पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री धामी उत्तराखंड के सपने के साथ समाज और सबके विकास और उम्मीदों को लगातार नई ऊर्जा दे रहे हैं। सीएम धामी के लिए 27 जनवरी को संकल्प पूरा करने का ऐतिहासिक दिन रहा। धामी सरकार ने इस दिन उत्तराखंड को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना दिया है। अगले दिन 28 जनवरी को उत्तराखंड में पहली बार 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की शुरुआत हुई। इस आयोजन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री धामी की सराहना की। राष्ट्रीय खेलों की ओपनिंग सेरिमनी देहरादून के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में भव्य और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ शुरू हुई।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सफलता के शिखर पर हैं और नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। सीएम धामी के नेतृत्व में ऐतिहासिक और अतुलनीय फैसलों से उत्तराखंड तेजी के साथ विकास के विजयपथ पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री धामी उत्तराखंड के सपने के साथ समाज और सबके विकास और उम्मीदों को लगातार नई ऊर्जा दे रहे हैं। इससे उत्तराखंड ने पूरे भारत में एक शक्तिशाली प्रदेश के रूप में पहचान बना ली है। वर्ष 2025 उत्तराखंड के लिए कई ऐतिहासिक उपलब्धियों का साल होने जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी के मार्गदर्शन में देवभूमि लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये उपलब्धियां सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, बल्कि प्रगति की एक मजबूत नींव भी हैं। साल 2025 की शुरुआत जनवरी में सीएम धामी के लिए उपलब्धियों भरी रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात को कई बार कह चुके हैं कि, 2025 उत्तराखंड के लिए नई उपलब्धियों वाला ऐतिहासिक वर्ष होगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस वर्ष उत्तराखंड पूरी तरह युवा हो जाएगा, क्योंकि राज्य अपने गठन के 25 वर्ष पूरे कर लेगा। उन्होंने कहा कि युवा राज्य पूरे जोश और उत्साह के साथ नई गति प्राप्त करेगा और हम राज्य के रजत जयंती वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए 27 जनवरी को संकल्प पूरा करने का ऐतिहासिक दिन रहा। धामी सरकार ने इस दिन उत्तराखंड को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना दिया है। इस कानून के आने के बाद अब राज्य में हलाला और बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है वहीं शादी या तलाक का रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। लिव इन में रहने के लिए माता-पिता की सहमति एवं रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होगा। उसके अगले दिन 28 जनवरी को उत्तराखंड में पहली बार 38वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन की शुरुआत हुई। इसके साथ निकाय चुनाव में भी भाजपा को उत्तराखंड के 11 नगर निगम में से 10 पर विजय का परचम लहराया। राष्ट्रीय खेल के आयोजन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री धामी की पीठ भी थपथपाई। राष्ट्रीय खेलों की ओपनिंग सेरिमनी देहरादून के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में भव्य और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ शुरू हुई। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पीएम मोदी ने इस दौरान राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। इस बात पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि यह उत्तराखंड के गठन का 25वां वर्ष है, देश भर के युवा इस युवा राज्य में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम में 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की सुंदर तस्वीर प्रदर्शित हुई। उन्होंने कहा कि इस बार राष्ट्रीय खेलों में कई स्थानीय खेलों को शामिल किया गया है और थीम 'ग्रीन गेम्स' है, क्योंकि इसमें पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं का उपयोग किया गया है। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान बताया कि ट्रॉफियां और पदक भी ई-कचरे से बने हैं और प्रत्येक पदक विजेता के नाम पर एक पौधा लगाया जाएगा। उत्तराखंड पहली बार इतने बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। इसे देखते हुए पीएम मोदी ने सराहना की और कहा कि यह अपने आप में महत्वपूर्ण उपलब्धि

है, इससे रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे और स्थानीय युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। उन्होंने आग्रह किया कि उत्तराखंड को विकास के नए रास्ते तलाशने चाहिए, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था केवल चार धाम यात्रा पर निर्भर नहीं रह सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार इन तीर्थयात्राओं का आकर्षण बढ़ाने के लिए लगातार सुविधाएं बढ़ा रही है, हर सीजन में तीर्थयात्रियों की संख्या नए रिकॉर्ड बना रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में शीतकालीन आध्यात्मिक यात्राओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इस दिशा में नए कदम उठाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की और इन शीतकालीन यात्राओं का हिस्सा बनने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने देश भर के युवाओं को सर्दियों के दौरान उत्तराखंड आने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि यहां तीर्थयात्रियों की संख्या कम होती है और साहसिक गतिविधियों के लिए कई अवसर होते हैं। उन्होंने सभी एथलीटों से राष्ट्रीय खेलों के बाद इन अवसरों का पता लगाने और लंबे समय तक देवभूमि के आतिथ्य का आनंद लेने का आग्रह किया। 38वें राष्ट्रीय खेल रजत जयंती वर्ष के दौरान उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित किए जा रहे हैं। ये खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों में 36 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश भाग लेंगे। गौरतलब हो, 17 दिनों में 35 खेल विधाओं की प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। इनमें 33 खेलों के लिए पदक दिए जाएंगे, जबकि दो प्रदर्शनी खेल होंगे। योग और मल्लखंब को पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है। इस आयोजन में देश भर से 10,000 से अधिक एथलीट भाग ले रहे हैं। इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों की थीम ''हरित खेल'' है। आयोजन स्थल के पास स्पोर्ट्स फॉरेस्ट नामक विशेष पार्क विकसित किया जाएगा, जहां एथलीटों और मेहमानों द्वारा 10,000 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे।

इसी महीने शुरू होने जा रहे बजट सत्र में धामी सरकार लाएगी भू-कानून

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। इसी फरवरी महीने के दूसरे पखवाड़े में उत्तराखंड में बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। धामी सरकार इस बजट सत्र के दौरान भू-कानून लाने की तैयारी शुरू कर चुकी है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की है कि उनकी सरकार अगले बजट सत्र में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप एक वृहद भू-कानून लेकर आएगी। यह कदम राज्य में भूमि के दुरुपयोग और बाहरी व्यक्तियों द्वारा अनियंत्रित जमीन खरीद को रोकने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। वर्तमान में उत्तराखंड में भूमि खरीद के नियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के तहत संचालित होते हैं। इस कानून के अनुसार, राज्य से बाहर का कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड में बिना अनुमति के 250 वर्गमीटर तक आवासीय भूमि खरीद सकता है। औद्योगिक और कृषि भूमि के लिए, विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। हालांकि, उत्तराखंड के स्थायी निवासियों के लिए जमीन खरीदने पर कोई सीमा नहीं है, यानी वे कितनी भी जमीन खरीद सकते हैं। नए भू-कानून के तहत यदि कोई बाहरी व्यक्ति 250 वर्गमीटर से अधिक भूमि खरीदता है, तो उसकी जांच की जाएगी और नियम तोड़ने पर जमीन सरकार में निहित की जाएगी। इसके अलावा, औद्योगिक या अन्य प्रयोजनों के लिए 12.50 एकड़ तक की भूमि खरीदने पर भी यही शर्त लागू होगी। इस सख्त कानून का उद्देश्य भूमि के दुरुपयोग को रोकना है। यदि किसी व्यक्ति ने उद्योग लगाने के नाम पर जमीन खरीदी है और उसका उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया है, तो ऐसी जमीन को सरकार में निहित करने की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 17 से 20 फरवरी के बीच हो सकता है। प्रदेश सरकार ने एक बार फिर जनभावनाओं के अनुरूप बजट बनाने की पहल की है। आगामी बजट पर सुझाव के लिए प्रदेश सरकार हितधारकों के साथ संवाद कार्यक्रम करेगी। महत्वपूर्ण सुझावों को सरकार बजट में भी शामिल करेगी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के अनुसार, इन सुझावों को संकलित कर संबंधित विभागों को भेजा जाएगा, ताकि इनमें से बेहतर सुझावों को बजट में शामिल किया जा सके।

देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय में यूसर्क सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बॉयोइन्फोर्मेटिक्स का उद्घाटन

उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र (यूसर्क) द्वारा देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय के परिसर में स्थापित किए गए 'यूसर्क सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बॉयोइन्फोर्मेटिक्स' का उद्घाटन मुख्य यूसर्क की निदेशक प्रोफेसर (डॉ) अनीता रावत द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्राफेसर रावत ने अपने संबोधन में कहा की यूसर्क के द्वारा स्थापित यह उत्कृष्ट केंद्र विद्यार्थियों में बायोइनफॉर्मेटिक्स विषय में न केवल उनके पाठ्यक्रम में सहायता करेगा बल्कि उनको प्रयोगात्मक रूप से प्रशिक्षित भी करेगा और उनके करियर को एक दिशा प्रदान करने का कार्य करेगा। उन्होंने बॉयोइन्फोर्मेटिक्स के तेजी से विकसित होते क्षेत्र की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला और छात्रों को इस विषय में अनुसंधान करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, ''आज के समय में बॉयोइन्फोर्मेटिक्स स्वास्थ्य, पर्यावरण और कृषि जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है। इस केंद्र के माध्यम से देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय ने केवल छात्रों को एक अद्वितीय मंच देगा बल्कि उभरती हुई तकनीकों में योगदान करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर (डॉ) जगमोहन सिंह राणा ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि आज हमारे विद्यार्थियों को विज्ञान की नई-नई विधाओं से परिचित कराने की आवश्यकता है। उनमें विज्ञान के प्रति अभिरुचि विकसित करनी होगी साथ ही साथ भारतीय ज्ञान विज्ञान को भी आत्मसात करना होगा। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष श्री संजय बंसल, कुलपति प्रोफेसर प्रीति कोठियाल एवं विश्वविद्यालय के शिक्षक गण उपस्थित रहे।

स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में धामी सरकार का बड़ा फैसला

राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज में पर्ची, बेड और एंबुलेंस का एक समान शुल्क

धामी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में आम जनता को बड़ी राहत दी है। प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों से अब एक समान यूजर चार्ज लिया जाएगा। ओपीडी, आईपीडी पर्ची बनाने से लेकर बेड और एंबुलेंस का एक समान शुल्क किया जायेगा। प्रदेश में पांच राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून, श्रीनगर, हरिद्वार, हल्द्वानी व अल्मोड़ा में संचालित हैं। इसके अलावा निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर व पिथौरागढ़ के संबद्ध चिकित्सालय भी संचालित हैं। इन मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में मरीजों का पंजीकरण शुल्क, बेड, एंबुलेंस व अन्य पैथोलॉजी जांच की दरें अलग-अलग हैं। धामी सरकार ने राजकीय चिकित्सालयों की तर्ज पर मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में यूजर चार्ज की एक समान दरें लागू करने का निर्णय लिया है। इसका सीधा लाभ इलाज के लिए आये मरीजों को मिलेगा।

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज में यूजर चार्जेज में एकरूपता लाने हेतु एक समान दर तय की गयी है। इससे पूर्व सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में यूजर चार्जेज की दरें भिन्न-भिन्न थी, जो कि संबंधित संस्थानों की स्थापना के समय निर्धारित की गयी थी। स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने बताया कि एक समान यूजर चार्जेज होने से संपूर्ण राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एकरूपता आने के साथ-साथ मरीजों को नवीन दरों का लाभ मिल सकेगा। उत्तराखण्ड राज्य के संपूर्ण जिला चिकित्सालयों में भी पूर्व

यूजर चार्ज की ये होंगी दरें

शुल्क का विवरण	दरें यप्रति मरीज)
ओपीडी पंजीकरण	20 रुपये
आईपीडी पंजीकरण	50 रुपये
जनरल वार्ड	25 रुपये
प्राइवेट वार्ड	300 रुपये
एसी वार्ड	1000 रुपये

से यही दरें निर्धारित की गयी है।

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों में यूजर चार्जेज के माध्यम से जो धनराशि प्राप्त होगी उसका उपयोग आम जनता की सुविधाओं हेतु व्यय किया जायेगा। जैसे..........

1. रैन बसेरों का निर्माण एवं रख रखाव।
2. चिकित्सा क्षेत्र में शोध एवं अनुसंधान कार्य।
3. चिकित्सा शोध छात्रों को प्रोत्साहन।
4. बाल रोग विभागान्तर्गत दुग्ध बूथ।
5. दिव्यांगजनों हेतु सुविधाओं का विस्तारीकरण।
6. पिंक शौचालयों का निर्माण।

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि नई दरें लागू होने के बाद सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी पर्ची शुल्क 20 रुपये और आईपीडी पर्ची शुल्क 50 रुपये लिया जाएगा। मेडिकल कॉलेजों में जनरल वार्ड में प्रति बेड के 25 रुपये, प्राइवेट वार्ड में 300 रुपये और एसी वार्ड प्रति बेड के 01 हजार रुपये शुल्क लिया जाएगा। एंबुलेंस का किराया पांच किमी. तक 200 रुपये होगा। इसके बाद प्रति किमी. 20 रुपये लिया जाएगा। रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजी जांच सीजीएचएस दरों पर राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, डायलिसिस की दरें केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना यसीजीएचएस) दरों के समान होंगी।

गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी को मिला तीसरा स्थान

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी बधाई

कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में 'सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल' पर आधारित उत्तराखंड की झांकी को लोगों की पसंद के आधार पर देश में तीसरा स्थान मिला है। गुजरात की झांकी 'स्वर्णिम भारत: विकास और विरासत' को प्रथम तथा उत्तर प्रदेश की झांकी महाकुंभ 2025- स्वर्णिम भारत विकास और विरासत को द्वितीय स्थान मिला।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड की झांकी को तीसरा स्थान मिलने पर प्रदेशवासियों और इसमें प्रतिभाग करने वाले सभी कलाकारों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की झांकी ने कर्तव्य पथ पर सभी का ध्यान आकर्षित किया। उत्तराखण्ड की झांकी में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और यहां के साहसिक खेलों को बखूबी प्रस्तुत किया गया। राज्य सरकार द्वारा पर्यटकों को सुरक्षित और सुखद यात्रा के लिए हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पूरे समर्पण के साथ कार्य किये जा रहे हैं।

महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी ने कहा कि कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी में राज्य से 16 कलाकारों ने भाग लिया। झांकी में उत्तराखण्ड की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को दर्शाती प्रसिद्ध ऐपण कला, उत्तराखण्ड के साहसिक खेलों एवं साहसिक पर्यटन को चित्रित किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और साहसिक खेलों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए गणतंत्र दिवस की परेड में झांकी के रूप में प्रदर्शित करने का निर्णय लिया गया।

संबद्धता विस्तारण पत्र न मिलने के कारण राज्य के हजारों युवा छात्रवृत्ति से वंचितः डॉ. सुनील अग्रवाल

निजी कॉलेज एसोसिएशन उत्तराखंड की एक बैठक आज आईटीएम कॉलेज चकराता रोड में संपन्न हुई बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. सुनील अग्रवाल ने की बैठक की जानकारी देते हुए डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने बताया की निजी कॉलेज एसोसिएशन की बैठक में कॉलेजों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई जिनमें प्रमुख रूप से कॉलेजो को संबद्धता विस्तारण लैटर समय से प्राप्त ना होना, जिसके कारण छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है और कॉलेजों कि साख पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, पुराने कॉलेजों की स्थाई संबद्धता, संबद्धता विस्तारण के नियमों में शासन द्वारा किए गए अव्यवहारिक परिवर्तन, समर्थ पोर्टल के दायरे में सभी विष्ठविद्यालयों निजी विष्ठविद्यालय को भी शामिल करने, श्री देव सुमन और कुमाऊं विष्ठविद्यालय से संबद्ध इ.मक कॉलेज में खाली सीटों एनसीटीई के मानक अनुसार पर प्रवेश की अनुमति इत्यादि विषयों पर विस्तार से प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी बैठक को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. सुनील अग्रवाल ने कहा की कॉलेजों को संबद्धता विस्तारण लेटर समय से ना मिल पाने के कारण कॉलेजो को होने वाली समस्याओं के लिए माननीय राज्यपाल महोदय माननीय मंत्री जी एवं शासन के अधिकारियों से मिलकर पुराने कॉलेजों की स्थाई मान्यता के संबंध में वार्ता की जाएगी और संबद्धता विस्तारण से संबंधित विभिन्न मुद्दो पर संबंधित अधिकारियों से व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने पर अपना पक्ष रखा जाएगा इसके साथ-साथ एक प्रदेश एक प्रवेश की नीति के तहत समर्थ पोर्टल के दायरे में सभी सरकारी और निजी विष्ठविद्यालयों को शामिल करने की मांग की जाएगी श्री देव सुमन विष्ठविद्यालय एवं कुमाऊं विष्ठविद्यालय से संबद्ध इ.मक कॉलेजों में खाली सीटों पर एनसीटीई के मानक के अनुसार प्रवेश करने के लिए कॉलेजों का पक्ष रखा जाएगा उन्होंने कहा कि उपरोक्त विषयों पर विष्ठविद्यालयों के कुलपतियों से भी वार्ता की जाएगी जिससे विभिन्न विषयों पर कॉलेजों का पक्ष रखते हुए व्यवहारिक दृष्टिकोण की अपेक्षा रहेगी उन्होंने कहा कि जो कॉलेज लंबे समय से अस्तित्व में है वह सभी एफीलिएशन के समय के मानकों को पूरा करते हैं और उनका समय-समय पर विष्ठविद्यालय के प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण भी होता रहता है इसलिए अब उन पर अव्यवहारिक मानकों में परिवर्तन उचित नहीं है बैठक में संगठन के सचिव निशांत थपलियाल, कोषाध्यक्ष अजय जसोला, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, कमल साहनी, जितेंद्र यादव, सुदेश शर्मा सहित देहरादून एवं रुड़की के कॉलेजों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

उमेश कुमार की विधानसभा सदस्यता निरस्त की जाएः पहाड़ अगेंस्ट करप्शन

देहरादून आज पहाड़ अगेंस्ट करप्शन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ समाजसेवी रविंद्र सिंह आनंद ने उत्तरांचल प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर उत्तराखंड में चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामे जो की तथा कथित पत्रकार एवं विधायक खानपुर उमेश कुमार एवं पूर्व विधायक खानपुर कुंवर प्रणब सिंह चौंपियन के मध्य चल रहा है, जिसमें दोनों द्वारा गाली गलौज करते हुए शास्त्रों का सरेआम प्रदर्शन किया गया यही नहीं बल्कि चौंपियन द्वारा फायरिंग तक की गई पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्षा श्रीमती रितु खंडूरी से इस पूरे प्रकरण में विधायक उमेश कुमार की संलिप्तता होने पर विधायक खानपुर उमेश कुमार की विधानसभा सदस्यता निरस्त की जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि विधायक द्वारा गाली गलौज एवं शास्त्र लहराना किसी भी जनप्रतिनिधि के निम्न स्तर के आचरण को दर्शाता है इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष कार्रवाई करते हुए उनकी विधानसभा सदस्यता निरस्त कर दें।

उन्होंने कहा कि विधायक समाज का दर्पण होता है और उसको देखकर युवा प्रेरित होते हैं लेकिन विधायक उमेश कुमार द्वारा इस प्रकार गाली गलौज करते हुए शास्त्रों को लहराना जैसी नीच हरकत को देवभूमि में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इसलिए उनकी विधानसभा सदस्यता निरस्त की जानी चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि निर्वाचन आयोग को भी इसका संज्ञान लेते हुए विधायक उमेश कुमार एवं प्रणव चौंपियन दोनों पर आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगा देनी चाहिए जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जा सके कि यदि जनप्रतिनिधि अपना रवैया अपराधियों जैसा रखेंगे तो निर्वाचन आयोग ऐसी कठोर कार्रवाई भी कर सकता है उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में किए गए इन दोनों के कृतियों पर अपना स्टैंड क्लियर करें उन्होंने कहा जिस प्रकार से मुख्यमंत्री धामी के साथ दोनों की नजदीकिया सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है उससे तो साफ जाहिर होता है कि उन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त है।

उन्होंने कहा जिस प्रकार सोशल मीडिया पर दोनों गाली देते हुए और शास्त्र लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं वह बहुत अशोभनीय है इसलिए महिला एवं बाल विकास आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए।

उन्होंने मानवाधिकार आयोग से भी इस पूरे प्रकरण में संज्ञान लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का रवैया, बर्ताव और आचरण इन दोनों माननीयों ने दिखाया है देवभूमि उत्तराखंड की जनता ऐसे दोनों जनप्रतिनिधियों का बहिष्कार कर में इनको धूल चटाने का काम करें उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहां इस प्रकार की गाली गलौज एवं शास्त्रों का प्रदर्शन करना चिंता का विषय भी है उन्होंने कहा उत्तराखंड में इस प्रकार की घटनाओं को देखकर के पूरे उत्तराखंड वासियों का सर शर्म से झुक गया है और पूरे भारत में उत्तराखंड के साथ को भट्ट लगा है जिसके लिए उमेश कुमार एवं चौंपियन समान रूप से दोषी हैं इसलिए देवभूमि उत्तराखंड की जनता इन दोनों को हर प्लेटफार्म से नकार दे अंत में उन्होंने मांग की कि दोनों पर कानून कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

राज्यपाल ने 'गोल्डन की आशा स्कूल' का भ्रमण किया।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से मुलाकात की और स्कूल की गतिविधियों की जानकारी ली।

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने गुरुवार को बीरपुर में 14 इन्फैंट्री डिवीजन द्वारा संचालित 'गोल्डन की आशा स्कूल' (Golden Key Asha School) का भ्रमण किया। बीरपुर छावनी में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संचालित इस स्कूल में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं। राज्यपाल ने भ्रमण के दौरान प्रत्येक कक्षा में जाकर बच्चों से बातचीत की और उनकी गतिविधियों एवं शिक्षण पद्धतियों की जानकारी ली। प्रधानाचार्या सामरा मिर्जा ने स्कूल द्वारा संचालित विभिन्न पहलों और कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराया, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाए जा रहे हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के उत्साह और सकारात्मकता से अभिभूत होकर, राज्यपाल ने विद्यालय के उत्कृष्ट प्रबंधन की सराहना की। उन्होंने प्रधानाचार्या और विशेष शिक्षकों की टीम द्वारा बच्चों के समग्र विकास के लिए किए जा रहे सराहनीय प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इन बच्चों को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन यापन में सहायता करने वाले सभी लोग अत्यंत पुनीत कार्य कर रहे हैं, समाज के अन्य लोगों को भी इस प्रकार के कार्यों में सहभागिता करने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने बच्चों को मिठाइयाँ और उपहार भी दिए साथ ही स्कूल हेतु 1.25 लाख रुपये वित्तीय सहायता का चेक भी दिया। 'गोल्डन की आशा स्कूल' (Golden Key Asha School) के भ्रमण के पश्चात, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने 14 इन्फैंट्री डिवीजन के जवानों और अधिकारियों से मुलाकात की और उनसे संवाद किया। उन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा और सेवा में उनके अनुकरणीय समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय सेना का 'राष्ट्र सर्वोपरि' का संकल्प अद्वितीय है। सैनिकों के साहस, निष्ठा और बलिदान पर पूरे देश को गर्व है। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा में भारतीय सेना का योगदान अमूल्य है और आपके त्याग से ही देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। कठिनतम परिस्थितियों में भी हमारे सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आप सभी सैनिकों का अदम्य साहस और अनुशासन प्रेरणादायक है, और आपकी सेवाएं राष्ट्र के लिए एक अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने सैनिकों के समर्पण को सलाम करते हुए कहा कि उनका देश प्रेम और कर्तव्यनिष्ठा असाधारण है। चाहे कैसी भी चुनौतियां हों, वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करते हैं। राज्यपाल ने कहा कि समूचा राष्ट्र उनकी बहादुरी और सेवा का ऋणी है, और उनकी प्रतिबद्धता से ही देश सुरक्षित और सशक्त बना हुआ है। इस अवसर पर प्रथम महिला श्रीमती गुरमीत कौर, मेजर जनरल नवीन महाजन, जीओसी, 14 डिवीजन, ब्रिगेडियर उपिंदर पाल सिंह, ब्रिगेड कमांडर 116 इन्फैंट्री ब्रिगेड, तथा अन्य सैन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने ली शारदा कॉरिडोर परियोजना समीक्षा बैठक

पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम रहे उपस्थित

उत्तराखण्ड सदन से शारदा कॉरिडोर परियोजना संबंध में बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि शारदा कॉरिडोर के कार्यों में तेजी लाई जाए। इस परियोजना के लिए जल्द ही भूमि का ज्वाइंट सर्वे किया जाए। शारदा कॉरिडोर क्षेत्र में भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र की स्टडी कर उनके सुरक्षात्मक उपायों पर कार्य किए जाएं। इस परियोजना के तहत धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शारदा नदी के किनारे रिवर फ्रंट का विकास किया जायेगा। जिसमें नदी किनारे घाटों का सौन्दर्यकरण, पर्यटकों और श्रद्धालुओं के अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शारदा और गंगा कोरिडोर का मुख्य उद्देश्य राज्य में धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना तथा श्रद्धालुओं को सुविधा देना है। उन्होंने कहा कि दोनों परियोजनाओं में अलग-अलग डिजाइन पर कार्य किये जायेंगे। शारदा कोरिडोर के तहत बुनियादी ढ़ांचे, पर्यटन और लोगों की आर्थिकी को बढ़ावा देने से संबधित अनेक कार्य किये जायेंगे।

इस अवसर पर पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज, राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल, सचिव श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, स्थानिक आयुक्त श्री अजय मिश्रा एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

नये अपराधिक कानूनों के मूल में है भारतीय दर्शन

राज्यपाल ले.ज. (रि.) गुरमीत सिंह

महामहिम राज्यपाल द्वारा नये अपराधिक कानूनों के दर्शन पर लिखी पुस्तक का विमोचन

राजभवन स्थित ऑडिटोरियम में आज उत्तरांचल विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रो0 राजेश बहुगुणा, राज्यपाल के विधि सलाहकार अमित सिरोही और लॉ कॉलेज देहरादून के डा0 वैभव उनियाल द्वारा लिखित पुस्तक 'भारत के नये अपराधिक कानूनों के पीछे की सोच' के विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया ग्या। महामहिम राज्यपाल ले0ज0 (से0नि0) गुरमीत सिंह इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे जबकि विश्वविद्यालय के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र जोशी, राज्यपाल सचिव श्री रविनाथ रमन, उपाध्यक्षा श्रीमती अनुराधा जोशी, कुलपति प्रो0 धर्मबुद्धि, प्राचार्य प्रो0 पूनम रावत बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे।

अपने सम्बोधन में महामहिम राज्यपाल ने कहा कि किसी भी कानूनी परिवर्तन के मूल में न्याय, निष्पक्षता और सामाजिक कल्याण के लोकाचार पर गहन चिंतन निहित है। हमारे रा'ट्र ने अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करने के लिए एक साहसिक और आवश्यक कदम उठाया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे शासन करने वाले कानून न केवल कुशल और मजबूत हैं बल्कि समकालीन वास्तविकताओं के अनुरूप भी हैं। यह पुस्तक उस प्रयास का प्रमाण है, जो इन ऐतिहासिक कानूनी परिवर्तनों के सिद्धांतों, विकास और उद्देश्यों पर व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि भारत के नये कानूनों के मूल में हैं भारतीय दर्शन। मैं कानूनी दर्शन और व्यावहारिक कार्यान्वयन के बीच की खाई को पाटने वाले इस विद्धत्तापूर्ण प्रयास के लिए लेखकों को बधाई देता हूँ। राष्ट्रवाद, स्वराज, तकनीकी प्रगति, सामाजिक प्रगति, पीड़ित कल्याण और सामुदायिक सेवा के नज़रिए से कानूनों का विश्लेषण करके, यह पुस्तक छात्रों, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और कानूनी चिकित्सकों के लिए एक अमूल्य संसाधन के रूप में कार्य करती है।

पुस्तक के एक लेखक प्रो0 राजेश बहुगुणा ने पुस्तक के विषय में बोलते हुए कहा कि उनकी पुस्तक भारत के नये अपराधिक कानूनों की युक्तियुक्तता और इनके पीछे के दर्शन पर आधारित है। पुस्तक को बारह चैप्टर में विभिक्त कर उन तमाम प्रश्नों पर चर्चा की गई है जो कि नये कानूनों के अस्तित्व में आने का कारण बने। उन्होंने कहा कि समाज में रह रहे लोगें के आचरण को नियंत्रित करने के लिए नियम कानूनों की आवश्यकता होती है। जैसे-जैसे समाज में सोच व परिस्थितियां बदलती हैं कानून में भी समुचित बदलाव की आवश्यकता होती है। राज्यपाल के विधि सलाहकार अमीत सिरोही ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया जबकि डा0 वैभव उनियाल द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से कार्यक्रम श्री धनंजय चतुर्वेदी प्रिंसिपल सैक्रेटरी लेजिसलेटिव ,वं पार्लियामेंटरी अफेयर्स, श्री मनीष मिश्रा, प्रिसिंपल जज फेमली कोर्ट एवं श्री राकेश सिंह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सहित राजभवन के अधिकारी, कर्मी व बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं भी उपस्थित थी।

डॉ दीपक कोहली को प्रतिष्ठित ''जगपति चतुर्वेदी बाल विज्ञान लेखन सम्मान'' से किया सम्मानित

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ द्वारा बाल साहित्य सम्मान, 2023 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत विशेष सचिव डॉ दीपक कोहली को उनकी उल्लेखनीय बाल विज्ञान साहित्यिक योगदान हेतु प्रतिष्ठित ''जगपति चतुर्वेदी बाल विज्ञान लेखन सम्मान'' से सम्मानित किया गया है। उल्लेखनीय है कि डॉ. दीपक कोहली बच्चों और किशोरों के लिए विगत 30 वर्षो से विज्ञान लेखन का कार्य कर रहे हैं। इनकी बाल विज्ञान की कई पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं, जिनका विमोचन माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनन्दीबेन पटेल द्वारा किया गया है। डॉ. कोहली के लगभग 600 बाल वैज्ञानिक लेख एवं विभिन्न बाल वैज्ञानिक क्विज भी प्रथिष्ठित पत्र- पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। आकाशवाणी से प्रसारित विभिन्न बाल कार्यक्रमो में बच्चों के लिये अनेकों विज्ञान वार्ताएँ प्रसारित हो चुकी हैं। डॉ. कोहली ने बताया कि विज्ञान बच्चों की सोच को परिष्कृत करके गुत्थियों से उलझने और निष्कर्ष तक पहुँचने का आसान माध्यम है। यदि बच्चों को बचपन से ही राष्ट्र भाषा हिन्दी में विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों से परिचित कराया जाये तो वे विज्ञान से जुड़ने लगते हैं, उनकी वैज्ञानिक सोच का विकास होता है और बच्चों में वैज्ञानिक गुण विकसित होते हैं।

जानिए कैसा होगा आपका यह सप्ताह

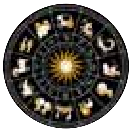
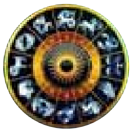

पं. दीपक प्रसाद, शास्त्री (मो. 9557730042)
(ज्योतिष, कर्मकाण्ड, धर्मिक अनुष्ठान आदि)

मेष राशि– संबंधों को अच्छे तरीके से निभाने के कारण आप सबके चहेते बने रहेंगे। अपनी योजनाओं पर काम करने के लिए अच्छा समय है। आपको अपनी कोशिशों के बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा। बाहरी लोगों का दखल न होने दें। प्रेम संबंधों में रोमांटिक माहौल रहेगा। मुलाकात भी हो सकती है। भाग्यशाली अंक– 3

वृषभ राशि– इस समय निजी कामों को भी ऊर्जा के साथ पूरा करने का जज्बा रहेगा। विद्यार्थियों की किसी विषय को लेकर चल गई समस्या का समाधान मिलेगा। कारोबारी गतिविधियों में सुधार होगा। विस्तार संबंधी नई योजनाएं बनेंगी। सूझबूझ से काम लेने की जरूरत है। व्यवस्थित दिनचर्या रखें। खान-पान पर ध्यान दें। भाग्यशाली अंक– 5

मिथुन राशि– अपनी प्रतिभा और क्षमता का भरपूर उपयोग करने का अवसर मिलेगा। परिवार के साथ धार्मिक कामों में समय बीतेगा। व्यवसाय में उतार-चढ़ाव रहेंगे। किसी अधीनस्थ कर्मचारी की वजह से कोई नुकसान होने की आशंका है। बेहतर होगा सभी महत्वपूर्ण काम अपनी देखरेख में करवाएं। प्रेम संबंधों से दूर रहें। भाग्यशाली अंक– 4

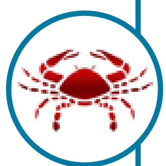

कर्क राशि– प्राकृतिक वातावरण में कुछ समय रहने से आपको नई ऊर्जा और स्फूर्ति महसूस होगी। बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। विरोधियों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। कपड़ों के व्यापारियों को अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है। प्रमोशन भी मिलने की भी संभावना है। नौकरी में विशेष काम की जिम्मेदारी मिल सकती है। भाग्यशाली अंक– 3

सिंह राशि– स्वास्थ्य संबंधी पुरानी समस्या से राहत महसूस करेंगे। शारीरिक और मानसिक सुकून मिलेगा। कोई विशेष प्रयोजन भी हल होने वाला है। पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी छुपी हुई प्रतिभा को रचनात्मक संबंधी कामों में लगाएं। पति-पत्नी में सामंजस्य की कमी रहेगी। परिवार के साथ मनोरंजन प्रोग्राम बन सकता है। भाग्यशाली अंक– 9

कन्या राशि– परिवार के साथ धार्मिक यात्रा का भी प्रोग्राम बन सकता है। बिजनेस का रुका काम फिर से शुरू हो सकता है। इंपोर्ट-एक्सपोर्ट संबंधी बिजनेस के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है। पूरी तरह कोशिश करते रहें। उपलब्धियों को हाथ से निकलने न दें। कानूनी गतिविधियों में दखलअंदाजी से मान-हानि हो सकती है। भाग्यशाली अंक– 4

तुला राशि– सामाजिक दायरा बढ़ेगा। लोगों की परवाह न करके खुद के कामों पर ध्यान दें। आपको नई उपलब्धियां मिल सकती हैं। रुका हुआ पैसा कलेक्ट करने के लिए समय अच्छा है। युवा अपने भविष्य की चिंता को लेकर परेशान हो सकते हैं। जीवनसाथी का आपके प्रति भावनात्मक लगाव संबंधों में मजबूती लाएगा। भाग्यशाली अंक– 1

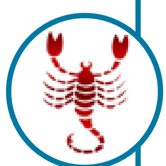

वृश्चिक राशि– करीबी संबंधी के विवाह का प्रस्ताव आने से खुशी का माहौल रहेगा। कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं, लेकिन आप समाधान ढूंढ लेंगे। व्यवसाय में महत्वपूर्ण और कुछ कड़े फैसले लेने की जरूरत है। खुद को साबित करने के लिए और मेहनत करें। पारिवारिक सदस्यों के तालमेल से घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। भाग्यशाली अंक– 2

धनु राशि– लक्ष्य पर फोकस रहेंगे तो जीत मिलेगी। सूझबूझ और विवेक से काम करने से हर काम आपके पक्ष में रहेगा। युवाओं को करियर से संबंधित शुभ समाचार मिलेगा। सरकारी नौकरी में किसी बात को लेकर अधिकारी नाराज हो सकते हैं। दोस्त और परिवार के साथ मौज मस्ती में समय बीतेगा। अविवाहित लोगों को कोई प्रपोजल मिल सकता है। भाग्यशाली अंक– 4

मकर राशि– महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय घर के बड़े लोगों की सलाह जरूर लें। ऐसा करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। घर के परिवर्तन संबंधी योजना पर काम शुरू हो सकता है। व्यापार में नए लोगों और नई पार्टियों के साथ डील करते समय सावधानी रखें। इस समय अपने काम की क्वालिटी बेहतर बनाने की जरूरत है। आसमानी, भाग्यशाली अंक– 1

कुंभ राशि– जमीन-जायदाद से जुड़े मामले आपसी तालमेल से सुलझाएं, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पैसों का लेनदेन स्थगित रखें। आपका पैसा फंस सकता है। युवाओं को किसी इंटरव्यू में सफलता न मिलने से निराशा हो सकती है। गैर कानूनी कामों में रुचि न लें। युवाओं को नौकरी मिलने की संभावना है। खानपान का विशेष ख्याल रखना होगा। भाग्यशाली अंक– 8

मीन राशि– अनुभवी लोगों की सलाह और मार्गदर्शन पर जरूर ध्यान दें। आपको आगे बढ़ने का कोई रास्ता मिल सकता है। कई बार जल्दबाजी और अति उत्साह में बना बनाया काम बिगड़ सकता है। जिससे पारिवारिक सुख-शांति पर असर पड़ेगा। अपने लक्ष्य के पर पूरा ध्यान रखें। त्वचा संबंधी दिक्कत उत्पन्न हो सकती हैं। भाग्यशाली अंक– 9

कौन हैं स्काई फोर्स फेम वीर पहाड़िया?

असिस्टेंट डायरेक्टर से लेकर बॉडी डबल तक, कैसे तय किया एक्टर का सफर

वीर पहाड़िया इस वक्त अपनी डेब्यू फिल्म स्काई फोर्स को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इस मूवी में वो अक्षय कुमार के साथ नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा तेज हो गई है। फिल्म में उनके काम को ऑडियंस काफी पसंद कर रही है। मगर क्या आपको पता एक्टर इससे पहले वरुण धवन के साथ फिल्म भेड़िया में काम कर चुके हैं।

अक्षय कुमार अपनी साल 2025 की पहली फिल्म के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर चुके हैं। स्काई फोर्स में एक बार वो आर्मी मैन के किरदार में नजर आ रहे हैं। मगर इस बार उनके साथ एक नया चेहरा भी पर्दे पर नजर आ रहा है जिसके बारे में ऑडियंस और ज्यादा जानना चाह रही है।

'स्काई फोर्स' के जरिए वीर पहाड़िया

बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा है। अगर आपको भी यही लग रहा है तो चलिए आपकी जानकारी को और बढ़ाते हैं। वीर पहाड़िया ने स्काई फोर्स से पहले फिल्म असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर चुके हैं और इतना ही नहीं वो एक मशहूर अभिनेता के बॉडी डबल भी रह चुके हैं।

कौन हैं वीर पहाड़िया?

'स्काई फोर्स' का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही वीर पहाड़िया चर्चा में आ गए थे। ट्रेलर में उनकी दमदार एक्टिंग और एक्शन स्टंट ने दर्शकों के बीच उनको लेकर दिलचस्पी बढ़ा दी थी। बता दें कि वीर पहाड़िया बिजनेस टाइकून संजय पहाड़िया और स्मृति संजय शिंदे के बेटे हैं। उनके दादा सुशील कुमार शिंदे हैं जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।

वीर पहाड़िया की एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने लंदन की रीजेंट यूनिवर्सिटी से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले वीर पहाड़िया एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं।

एक्टर से पहले बने थे डायरेक्टर

जी हीं, अभिनेता ने साल 2022 में आई फिल्म भेड़िया में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया था। इस फिल्म के निर्देशक अमर कौशिक थे। इतना ही नहीं वीर बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन के बॉडी डबल का भी काम फिल्मों में कर चुके हैं। बता दें कि वीर पहाड़िया का नाम सैफ अली खान की बेटी और एक्ट्रेस सारा अली खान के साथ जुड़ चुका है। हालांकि दोनों ने कभी भी इस रिश्ते पर कोई बयान जारी नहीं किया। स्काई फोर्स में दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री को काफी पसंद किया जा रहा है। स्काई फोर्स की बात करें तो यह भारतीय पायलटों के जज्बे को समर्पित फिल्म है।

स्काई फोर्स का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन?

फिल्म का निर्देशन अभिषेक अनिल कपूर और संदीप केवलानी ने किया है। मूवी को 24 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 11.25 करोड़ की कमाई की है। पहले दिन के लिहाज से ये फिल्म के लिए अच्छी शुरुआत हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, खबर लिखे जाने तक फिल्म ने दूसरे दिन फिलहाल 81 लाख का बिजनेस कर लिया है। अक्षय कुमार और वीर पहाड़िया के अलावा फिल्म में सारा अली खान, निमरत कौर ने अहम भूमिका निभाई है। अब देखना है 26 जनवरी के मौके पर ये अपने बिजनेस में कितना उछाल लाती है।

R.N.I.: UTTHIN/2010/41629 Postal Regd. UA/DO/DDN/01/2025-2027

धन्यवाद उत्तराखंड

सफल प्रकाशन का गौरवशाली 14वाँ वर्ष

उत्तराखंड से प्रकाशित एकमात्र समाचार साप्ताहिक पत्रिका

दिव्य हिमगिरि

हिमालयी राज्यों की पहली साप्ताहिक पत्रिका

नज़र सब पर

मूल्यः रु 15/– मात्र

नए कलेवर में प्रत्येक रविवार

प्रत्येक रविवार

दिव्य हिमगिरि

संपादकीय कार्यालय : 6, म्युनिसिपल रोड, बाला हिसार स्कूल के सामने, डालनवाला देहरादून यउत्तराखंड)

मोबाइल : +91 8433456398, 9410353164

Email: divyahimgiriddnègmail.com